web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार, 05 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 186

महत्वपूर्ण एवं खास

सरकार ने विनय क्वात्रा को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। अगले विदेश सचिव के तौर पर विनय क्वात्रा के नाम पर मुहर लग गई है। क्वात्रा फिलहाल नेपाल में भारत के राजदूत हैं। क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे जो अप्रैल के अंत में रिटायर होने वाले हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने नए विदेश सचिव के तौर पर विनय क्वात्रा के नाम को मंजूरी दे दी है।

किसान पर धारदार हथियार से हमला, मौत

सतना (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सतना जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां खेत पर बने घर में सो रहे किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पहले किसान के सिर से लेकर गुप्तांग तक धारदार हथियार से हमला किया गया। इस पर भी जब वह नहीं मरा तो आरोपियों ने उसका गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार, सतना जिले के मैहर थानाक्षेत्र के भैसासुर गांव के रहने वाले 50 साल के महेश साहू अपने खेत पर बने घर (अहरी) में सो रहे थे। देर रात हमला कर आरोपियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह मृतक की पत्नी और बेटा जब खेत पहुंचे तो अहरी का अंदर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृतक का शव लहूलुहान हालत में खटिया के नीचे पड़ा था। इसके बाद तत्काल डायल 100 को सूचना दी गई। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि महेश साहू के शरीर में सिर से लेकर गुप्तांग तक हमला किया गया है। कई जगह धारदार हथियार से हमले के निशान मिले है। इसके अलावा पत्थर पटकने के निशान भी पाए गए हैं। यही नहीं गले दबाने की कोशिश भी की गई। मृतक महेश के परिवार में पत्नी बुद्धिबाई, दो बेटे और दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है। एक बेटी ने गांव में ही प्रेम विवाह किया था। दोनों बेटे अविवाहित हैं। मृतक ने पिछले साल ही खेत पर बोरवेल कराई है जिसकी तकवारी के लिए वो रोजाना खेत पर बने घर में रुकते थे। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे : सीएम

देहरादून (आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे और ऑफिस टॉइम में पूर्ण मनोयोग से कार्य करें। समय पर कार्यालय न आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कारवाई की जाय। जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाय। जनता एवं जन प्रतिनिधियों के फोन अवश्य रिसीव करें। यदि किसी वजह से फोन रिसीव न कर पायें तो कॉल बैक जरूर करें।

यौन उत्पीड़न का विरोध करना पड़ा महंगा, देवर ने महिला व बच्चे को जलाया जिंदा

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के नाथम गांव के पास शनिवार 2 मार्च को एक महिला और उसके डेढ़ साल के बच्चे को उसके देवर ने जिंदा जला दिया। पीड़ितों की पहचान 22 वर्षीय अंजली और उसके बच्चे मलारविझी के रूप में हुई है। उसकी शादी दिहाड़ी मजदूर शिवकुमार से हुई थी, और वे एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते थे। शिवकुमार के भाई करुप्पैया (30) ने कथित तौर पर अंजली के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे प्रताड़ित भी करता था। शनिवार को जब अंजली भेड़-बकरियों के पास गई थी तभी करुप्पैया ने उसका पीछा किया और उसका यौन शोषण करने का प्रयास किया। उस समय शिवकुमार काम पर चला गया था। जब अंजली, जो अपने बच्चे के साथ थी, मदद के लिए चिल्लाई, तो कररूपैया ने उन दोनों को काट डाला। इसके बाद उसने दोनों घायलों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने करुप्पैया की पिटाई कर दी। इसके बाद उसे डिंडीगुल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पति शिवकुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने करुप्पैया के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया।

जम्मू-कश्मीर : लाल चौक और पुलवामा में आतंकी हमले, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को आतंकी हमला हुआ है। लाल चौक के मैसुमा में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है। इसके अलावा खबर है कि आतंकियों ने पुलवामा में भी स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। रविवार को ही सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास गांव से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए थे।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने गैर-स्थानीय दो लोगों को गोली मार दी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गैर-स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों का यह दूसरा हमला है। उन्होंने बताया, पुलवामा के लाजूरा में सोमवार दोपहर में आतंकवादियों ने पटलेश्वर कुमार और जाको चौधरी पर गोलियां चलायीं। दोनों बिहार के रहने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि और जानकारी की प्रतीक्षा है। इससे पहले आतंकवादियों ने रविवार की शाम पुलवामा के नौपोरा इलाके में दो गैर-स्थानीय मजदूरों को गोली मार दी थी। दोनों पंजाब के रहने वाले थे।

रविवार को भी भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को बड़ी सफलता मिली थी। संयुक्त कार्रवाई में पुंछ जिले में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे। जम्मू में रक्षा प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया, खुफिया

जानकारी के आधार पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स की पुंछ ब्रिगेड और एओजी पुंछ की तरफ से तहसील हवेली के नूरकोट गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था।

बयान के अनुसार, जवानों को दो एके-47 राइफल, एके-47 की दो मैगजीन, एक 223 बोर एके आकार की बंदूक और मैगजीन, एक चीनी पिस्तौल और मैगजीन, एके-47 के 63 राउंड्स, 223 बोर बंदूक के 20 राउंड और चीनी पिस्तौल के 4 राउंड बरामद किए गए थे।

अमशीपुरा मुठभेड़ मामले में सेना के कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाई शुरु, 3 नागरिकों को मारी थी गोली

भारतीय सेना ने एक कथित मुठभेड़ में शामिल कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल की शुरुआत की है, जहां जुलाई 2020 में जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपुरा गांव में 3 नागरिकों को आतंकवादी समझ लिया गया था। सेना ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंचयरी और सबूतों के मद्देनजर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की जरूरत है। इसके बाद सेना के कैप्टन भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले के 3 लोग, इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार 18 जुलाई, 2020 को शोपियां जिले में मारे गए और उन्हें आतंकवादी बताया गया था। लेकिन जैसे ही विरोध शुरू हुआ और कथित हत्याओं पर संदेह जताया गया, तो सेना ने तुरंत एक कोर्ट ऑफ इन्चयरी का गठन किया, जिसमें प्रथम दृष्टया सबूत मिले कि सैनिकों ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के तहत निहित शक्तियों से परे जाकर काम किया। फर्जी मुठभेड़ की खबर फैलने के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिसने कैप्टन सिंह सहित 3 लोगों के खिलाफ शोपियां जिले में फर्जी मुठभेड़ करने और 3 लोगों को मारने के लिए आरोप पत्र दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि कैप्टन सिंह ने मुठभेड़ के दौरान की गई बरामदगी के बारे में अपने वरिष्ठों और पुलिस को गलत जानकारी दी थी। पुलिस ने अपने आरोपपत्र में अन्य दो नाम ताबीश नजीर और बिलाल अहमद लोन शामिल किया, जो दोनों स्थानीय नागरिक हैं। कोर्ट ऑफ इन्चयरी के बाद साक्ष्यों का सारांश दिया गया, जो दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में पूरा हुआ। अक्टूबर 2020 में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीनों परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा।

दिल्ली को मिलेगी और रफ्तार, अक्षरधाम बनेगा एनसीआर का सबसे बड़ा ट्रैफिक जंक्शन

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में अक्षरधाम से सराय काले खां और गोल चक्कर पार्क (डीएनडी) तक दिल्ली-एनसीआर का सबसे बड़ा ट्रैफिक जंक्शन बनने जा रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब दो नए एक्सप्रेसवे भी जुड़ने जा रहे हैं। इनमें दिल्ली-मुंबई कनेक्टर और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए डीएनडी, रिंग रोड, आश्रम रोड और चिल्ला बॉर्डर का ट्रैफिक भी इसी जंक्शन पर पहुंचेगा। इससे प्रति दिन इन जंक्शनों के बीच 10-15 लाख पैसेंजर पर कार यूनिट (पीसीयू) का दबाव होगा। इसके अतिरिक्त रैपिड ट्रेन का भी सराय काले खां में जंक्शन बन रहा है, जिससे दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-सोनीपत और दिल्ली-अलवर कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा।

एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, रेल, बस अड्डा और रैपिड ट्रेन के जुड़ने पर पूरे जंक्शन में लोगों की सबसे ज्यादा आवाजाही होगी। इसी को ध्यान में रखकर सभी निर्माण एजेंसियां काम कर रही हैं। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है, जिससे व्यवस्थित तरीके से वाहनों की आवाजाही हो सके। यह रोड तीनों एक्सप्रेसवे और दिल्ली-नोएडा के ट्रैफिक को परिवर्तित करने और वाहनों को सही रोड पर भेजने का काम करेगी। सराय काले खां से अक्षरधाम और डीएनडी रोड के बीच ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए अभी रोड का काम रोका गया है। उसके कुछ लूप में परिवर्तन किया जाएंगे, जिससे नोएडा-दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक दिल्ली-मुंबई, मेरठ और देहरादून एक्सप्रेसवे पर जा सके। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए सोहना से सराय काले खां तक 60 किलोमीटर का कनेक्टर बनाया जा रहा है। कुल 90 कमी लंबे कनेक्टर को गोल चक्कर पार्क के निकट (डीएनडी) जोड़ा जाएगा।

आंध्र प्रदेश को मिला नया नक्शा, जिलों की संख्या दोगुनी होकर 26 हुई

अमरावती (आरएनएस)। आंध्र प्रदेश को सोमवार को एक नया प्रशासनिक नक्शा मिला। इसके मुताबिक राज्य में 13 नए जिले बनाए गए हैं। 13 नए जिलों के साथ आंध्र प्रदेश में कुल जिलों संख्या दोगुनी होकर 26 हो गई है। राज्य सरकार ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर शासन और सेवाओं के वितरण में सुधार होगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के 13 नए जिलों का शुभारंभ किया। रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार ने 13 जिलों को पुनर्गठित करके 13 नए जिले बनाए हैं। प्रदेश में राजस्व संभाग 72 हो गए हैं।

रेड्डी ने 2019 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह 25 लोकसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक को एक जिला बनाएगी।

ये हैं आंध्र के 13 नए जिले-

नव निर्मिति जिलों में पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, श्री सत्य साई, तिरुपति और अन्नामय्या शामिल हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को नए जिलों के नर्मिाण और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। नए जिलों के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय और अधिकारियों को तैयार कर लिया गया है। सरकार ने जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, संभागीय राजस्व अधिकारियों, आरडीओ और अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया है। नवसृजित 13 जिलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान की जा रही है।

इन लोगों के नाम पर हैं जिलों के नाम-

गौरतलब है कि सरकार ने नए जिलों में से एक का नाम अल्लूरी सीताराम राजू रखा जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सरकार ने एक अन्य जिले का नाम एनटीआर जिला (तेलुगू देशम पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाराव) भी रखा। अंतिम बार राज्य में 1979 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के रूप में एक नया जिला बनाया गया था।

मुख्यमंत्री ने नए जिलों का शुभारंभ करने के बाद कहा कि प्रशासन को उदार और आसान बनाने के लिए 13 जिलों को पुनर्गठित करके 13 नए जिले बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 13 जिलों के बनने से राज्य में अब 26 जिले हो गए हैं जो लोगों की बेहतर तरीके से सेवा करने और उन तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी नीति एक कुशल और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है और शहरों और गांवों में भी प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना है ताकि लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकें और पारदर्शी तरीके से काम कर सकें।

अनुराग ठाकुर ने प्रसारकों के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया और इसके साथ ही प्रसारण क्षेत्र में 'व्यवसाय में आसानी' का एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है, जिसके तहत प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों, अनुमतियों, पंजीकरणों आदि के लिए आवेदनों को शीघ्रता से दाखिल किया जा सकेगा और इन आवेदनों की जांच भी तेजी से पूरी की जा सकेगी।

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं इसे और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। प्रसारण सेवा पोर्टल आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में लगनेवाले समय को कम करेगा और आवेदकों को आवेदन

की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल आवेदकों की उपस्थिति की आवश्यकता को कम करेगा, जो पहले आवश्यक था और इस प्रकार मंत्रालय की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा। यह व्यवसाय में आसानी की दिशा में भी एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।

ठाकुर ने यह भी कहा कि सभी प्रकार के (360 डिग्री) डिजिटल समाधान; हितधारकों को अनुमति लेने, पंजीकरण के लिए आवेदन करने, आवेदनों पर नजर रखने, शुल्क की गणना करने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह पोर्टल निजी उपग्रह टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट संचालकों, एमएसओ, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों आदि से जुड़े सभी हितधारकों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

ठाकुर ने कहा यह पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मंत्र को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा; क्योंकि सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल यह वेब पोर्टल, प्रसारकों को शुरुआत से अंत तक (एंड-टू-एंड) के सभी समाधान केवल एक क्लिक पर प्रदान करता है। यह पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट संचालकों, 1700 मल्टी-सर्विस संचालकों, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस), 380 निजी एफएम चैनलों और अन्य को सीधे लाभ पहुंचाकर कारोबारी माहौल को बढ़ावा देगा और पूरे प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाएगा।

मंत्री ने उपस्थित लोगों को बताया कि पोर्टल के परीक्षण को अंतिम उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जल्द ही पोर्टल को राष्ट्रीय एकल खिडक़ी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यदि उद्योग जगत को कोई अन्य सुधार आवश्यक लगता है, तो मंत्रालय ऐसे सुधारों को शामिल करने के लिए भी तैयार है।

दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस : नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत विशेष पीएमएलए अदालत ने 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दे दी है। इससे पहले मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बेड, गद्दा और कुर्सी मुहैया कराने की उनकी याचिका को स्वीकार किया गया था।

वहीं, मलिक ने उन्हें तत्काल रिहा किए जाने की अपली वाली अंतरिम याचिका को खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वकील अंकुर चावला की ओर से तैयार की गई याचिका में मलिक ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के 15 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। विशेष अनुमति याचिका वकील वी डी खन्ना के जरिए दायर की गई है। बंबई उच्च न्यायालय ने मलिक को तत्काल रिहा करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि चूंकि विशेष पीएमएलए अदालत के उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है तो इससे यह आदेश गैरकानूनी या गलत नहीं हो जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से कथित तौर पर जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत इस साल 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद हिरासत में भेजना गैरकानूनी है।

विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल ने पूरे देश में फिर लहराया परचम

- देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अव्वल
- छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर, मात्र 0.6 प्रतिशत
- जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत
- नीतिगत फैसलों और बेहतर प्रबंधन ने घटाई राज्य की बेरोजगारी दर

रायपुर (आरएनएस)। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल ने पूरे देश में अपनी सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अव्वल है। राज्य सरकार के

नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही।

छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।

कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नये आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 05 वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत है।